डी. आर. सोमयाजुलु, सचिव डी. एल. एस. और अन्य

एस. ई. रेलवे हाउस बी एल डी जी. को-ओ सोसाइटी लिमिटेड विशाखापट्टनम

बनाम

अत्तिलियप्पल स्वामी और अन्य

(सिविल अपील सं. 10404/2014)

19 नवंबर, 2014

[टी. एस. ठाकुर, आदर्श कुमार गोल और आर. भानुमती, जे. जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश XLVII नियम 1 - क्षेत्राधिकार की समीक्षा-क्षेत्र-आयोजितःसमीक्षा न्यायालयों के पास केवल सीमित अधिकार क्षेत्र है जो या में उपयोग की जाने वाली भाषा द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाओं द्वारा सीमित है। आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी.-यह तीन निर्दिष्ट आधारों पर समीक्षा की अनुमति दे सकता है, अर्थात्ः- (i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज, जो उचित परिश्रम के बाद, आवेदक की जानकारी में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था; (ii) रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि; या (iii) किसी अन्य पर्याप्त कारण आरम्भतः-नई सामग्री की खोज के आधार पर समीक्षा के लिए आवेदन को बहुत सावधानी आरम्भतः माना जाना चाहिए और इआरम्भतः बहुत हल्के में नहीं दिया जाना चाहिए-तथ्यों पर, अपने स्वयं के आदेश और फिर शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम (यूएलसीआर अधिनियम) के तहत अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार करते हुए समीक्षा याचिका में, उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक 'ए' की संपत्ति का कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं था।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरि राम (2013) 4 एस. सी. सी. 280-संदर्भित।

केस कानून संदर्भित

(2013) 4 एस. सी. सी. 280	संदर्भित	पैरा 26

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल याचिका संख्या 10404/ 2014

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के डब्ल्यू. पी. एम. पी. सं. 1540/2009 समीक्षा याचिका में के दिनांक 30.04.2011 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल याचिका सं 10408/2014

गुरु कृष्ण कुमार, वी. वी. एस. राव, सीनियर अधिवक्ता , टी. वी. रत्नम, सुश्री जयश्री, गुंटूर प्रभाकर, जी. एन. रेड्डी, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

पी. पी. राव, प्रभु पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश बाबू, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, वाई. राजा गोपाल राव, सुश्री वाई. एफ. विस्मई राव, सुधीर के. रेड्डी, हितेंद्र नाथ रथ, अधिवक्ता, प्रतिवादीओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय आर. भानुमति, जे. द्वारा दिया गया था।

1. एस. एल. पी.(सिविल) सं. 9648/2013 में देरी को माफ कर दिया गया। दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति अनुदत्त दी गई।

2. ये अपीलें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश की शुद्धता को चुनौती देती हैं जो रिट अपील सं.1840/2008 दिनांक 30.4.2011 में समीक्षा आवेदन डब्ल्यू. पी. एम. पी. सं. 1540/2009 में पारित किया गया था, जिसमें 38,781 वर्ग किलोमीटर की सीमा निर्धारित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित 5.1.1982 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था। स्वर्गीय अट्टीली नरसयम्मा को अधिशेष भूमि के रूप में

और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.4.2001 द्वारा इस आधार पर पारित आदेश कि मृत व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्यवाही शुरू आरम्भतः ही पूरी तरह आरम्भतः अमान्य और गैर-स्थायी है।

3. इस मामले का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है। इन अपीलों के निर्धारण के दौरान तथ्यों और घटनाओं की एक भूलभुलैया हमारे सामने आती है। अनिवार्य रूप से, जिन मुख्य प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए, वे हैंः-

(i) शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (संक्षिप्त यू. एल. सी. आर. अधिनियम के लिए) की खंड 9 के तहत पारित अंतिम विवरण पर अट्टिली नरसय्यम्मा के कानूनी उत्तराधिकारियों को लागू न करने और अधिशेष भूमि को सरकार में निहित करने का प्रभाव; (ii) इस तरह निहित भूमि पर शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 (संक्षिप्त में 'निरसन अधिनियम 1999') का प्रभावः-

(क) राज्य सरकार के पास निहित 6 एकड़ भूमि की सीमा तक जो अपीलकर्ता सोसायटी को आवंटित की गई है क्योंकि सोसायटी ने भूमि के मालिकों के साथ बिक्री का समझौता किया है और 6 एकड़ के कब्जे में होने का दावा किया है;

(ख) शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 का अधिशेष भूमि की शेष सीमा पर प्रभाव।

4. हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले विवाद के सीमित दायरे के बावजूद, हमारे लिए पक्षों के बीच विवाद की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना आवश्यक है। अपीलार्थी-समिति ने एस. एन. सं. में 6 एकड़ की संपत्ति के संबंध में प्रथम प्रतिवादी,

अट्टिली नरसयम्मा की दादी के साथ 25.8.1974 पर बिक्री का समझौता किया। अपने सदस्यों को आवास भूखंड प्रदान करने के उद्देश्य से कप्पारदा गाँव, विशाखापत्तनम का 30/1 और 30/2 अट्टीली नरसय्यम्मा को रुपये 1,52,000-की बिक्री का प्रतिफल प्राप्त हुआ और भूमि का कब्जा अपीलार्थी-सोसायटी को सौंप दिया गया।अपीलार्थी-समिति ने विभिन्न तिथियों पर अन्य समझौता ज्ञापन/बिक्री समझौते भी किए थे, जिनका विवरण संबंधित स्थान पर भेजा जाएगा।इस बीच, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अधिशेष भूमि जोत लेने की मांग की।अट्टिली नरसय्यम्मा ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 6 (1) के तहत घोषणा दायर की। बेटों, बेटियों और पोते-पोतियों ने भी पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 6 (1) के तहत घोषणाएं दायर की हैं। उचित जांच के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत नोटिस के साथ खंड 8 (1) के तहत मसौदा बयान जारी किया, जिसमें के एस. सं.29/1,30/1,30/2 और 30/3 गाँव की सीमा 38781 वर्ग किलोमीटर तक कप्पारदा अतिरिक्त भूमि धारक के रूप में अट्टिली नरसय्यम्मा का अस्थायी रूप से निर्धारण किया गया।

5. यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत जारी किए गए नोटिस के जवाब में, स्वर्गीय अट्टिली नरसयम्मा को छोड़कर, इसमें पहले प्रतिवादी सहित सभी घोषणाकर्ताओं ने समान आपत्तियां दायर कीं। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, उद्घोषकों का प्रतिनिधित्व उनके वकील द्वारा से किया जाता था। व्यक्तिगत घोषणाकर्ताओं और उनके वकील को भी नोटिस जारी करके सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने 38781 वर्ग किलोमीटर की सीमा तक अतिरिक्त भूमि के धारक के रूप में अट्टिली नरसय्यम्मा को पाते हुए दिनांक 5.1.1982 का आदेश पारित किया। एमटीआरएस।सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, अटिली

नरसय्यम्मा ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 33 के तहत अपील दायर की। इस बीच, यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 9 के तहत अंतिम बयान जारी कर दिया गया था।यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 10 (1) के तहत अधिसूचना और खंड 10 (3) के तहत घोषणा जारी की गई थी और उन्हें क्रमशः 24.21983 और 22.10.1990 पर आंध्र प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। एटिली विश्वनाथ राव और एटिली पेडा वेंकट रमण मूर्ति ने डब्ल्यू. पी. सं.2696/1991 वाली एक याचिका दायर की है जिसे वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था।अपीलीय प्राधिकरण-भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त ने पहले प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अटिली नरसयम्मा के कानूनी उत्तराधिकारियों को औपचारिक रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया था और यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 33 के तहत दायर अपील को उसके दिनांक 24.4.2001 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

6. अपीलीय प्राधिकरण के दिनांक 24.4.2001 के आदेश को चुनौती देते हुए, अटिली पेडा वेंकट रमण मूर्ति और अटिली विश्वनाथ राव ने रिट याचिका संख्या 18340/2001 दायर की। उक्त रिट याचिका को दूसरे याचिकाकर्ता-अटिली विश्वनाथ राव के खिलाफ वापस ले लिया गया था। रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, अटिली पेडा वेंकट रमण मूर्ति की मृत्यु हो गई और इसमें पहले प्रतिवादी को मृतक पेडा वेंकट रमण मूर्ति के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया। उक्त रिट याचिका को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा 6.11.2008 पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कानूनी प्रतिनिधियों पर नोटिस की गैर-सेवा से कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ क्योंकि उन सभी के पास अटिली नरसय्यम्मा की ओर से अपनी आपत्तियां रखने का अवसर था और उन्होंने पूरी कार्यवाही में भाग लिया था।उक्त आदेश से व्यथित, पहले प्रतिवादी ने रिट अपील संख्या 1840/2008 को प्राथमिकता दी, जिसे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने

दिनांक 2.2.2009 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।इस बीच, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 आंध्र प्रदेश राज्य में 22.4.2008 पर राजपत्रित 27.3.2008 से लागू हुआ।प्रथम प्रत्यर्थी ने एक समीक्षा याचिका दायर की जो डब्ल्यू. पी. एम. पी. सं 1540/2009 के आधार पर डब्ल्यू. ए. सं.1840/2008 में आदेश की समीक्षा की मांग करती हैः- (i) कि अटिली नरस्यम्मा के कानूनी प्रतिनिधियों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था और 5.1.1982 दिनांकित आदेश अमान्य और अवैध है; (ii) शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के प्रभाव को खण्ड पीठ द्वारा विचार में नहीं लिया गया था।

7. उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका को मुख्य रूप आरम्भतः इस आधार पर स्वीकार किया कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मृतक अट्टिली नरसयम्मा की संपत्ति का कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं था और किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ की गई कोई भी कार्यवाही पूरी तरह आरम्भतः अमान्य है। उच्च न्यायालय ने तदनुसार अपने स्वयं के दिनांकित 2.2.2009 आदेश को दरकिनार कर दिया और परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांकित 5.1.1982 आदेश और दिनांकित 24.4.2001 अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों और दिनांकित 6.11.2008 विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को भी दरकिनार कर दिया।अपीलार्थी-समिति और विभाग के कहने पर दायर विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें समीक्षा याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की शुद्धता को चुनौती देती हैं।

8. अपीलकर्ता-समिति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री गुरु कृष्णकुमार ने कहा कि प्रथम प्रतिवादी सहित अट्टिली नरसयम्मा के बेटों, बेटियों, पोते-पोतियों ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम की धारा 6 (1) और 8 (3) के तहत जारी किए गए मसौदा बयान पर अपने बयान और आपत्तियां दायर की हैं और इस

प्रकार, अट्टिली नरसयम्मा के सभी कानूनी प्रतिनिधियों ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम के तहत कार्यवाही में भाग लिया था और कहा जा सकता है कि कानूनी उत्तराधिकारियों को औपचारिक नोटिस न देने के कारण उन्हें कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार को भूमि सौंपने और अपीलार्थी-समिति को 6 एकड़ भूमि के आवंटन पर जोर देते हुए, जी ओ एमएस संख्या 340 दिनांक 5.3.2003 और जी ओ एमएस सं. 1900 के माध्यम से दिनांक 20.12.2006, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि सोसायटी और सदस्य/आवंटी पहले से ही संपत्ति के कब्जे में हैं और शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि सोसाइटी को आवंटित भूमि की सीमा और उच्च न्यायालय समीक्षा याचिका को अनुमति देने में उचित नहीं था।

9. प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. वी. एस. राव ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और अटिली नरसयम्मा के अन्य कानूनी प्रतिनिधियों ने कार्यवाही में भाग लिया था और उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही की पर्याप्त जानकारी थी। डब्ल्यू पी सं.18340/2001 में एकल न्यायाधीश के फैसले और रिट अपील सं.1840/2008 द्वारा से हमें लेते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि नीचे की अदालतों ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि अटिली नरसयम्मा के कानूनी प्रतिनिधियों ने कार्यवाही में भाग लिया था और केवल भागीदारी के तथ्य को दबाकर, प्रतिवादी संख्या 1 ने समीक्षा के लिए पुनर्विचार आवेदन दायर किया। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अपनाया गया शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 (27.3.2008 पर) इस मामले में लागू नहीं है क्योंकि अधिशेष भूमि बहुत पहले यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के प्रावधानों के अनुसार सरकार में निहित है।

10. हमें जी ओ एमएस सं 1900 द्वारा से ले जा रहा है। दिनांक 20.12.2006, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. पी. राव, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश हुए। प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भूमि का आवंटन लंबित मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन होगा और अपीलार्थी-सोसायटी को मुकदमा संपत्ति के संबंध में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि अटिली नरसयम्मा की मृत्यु 15.9.1977 पर हुई और यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत, 30.11.1977 पर जारी मसौदा बयान अटिली नरसयम्मा को नहीं दिया जा सकता था और चूंकि अटिली नरसयम्मा के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था और उन पर कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए मृत व्यक्ति के खिलाफ सभी कार्यवाही अवैध और शुरू आरम्भतः ही अमान्य हैं। यह आगे तर्क दिया गया कि चूंकि निचली अदालतों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण इस प्रासंगिक पहलू की सराहना करने में विफल रहे हैं कि यू. एल. सी. आर. अधिनियम (दिनांक 30.11.1977) की खंड 8 (3) के तहत जारी किया गया नोटिस घोषणाकर्ता-अटिली नरसयम्मा पर लागू नहीं किया गया था, इसलिए पहले प्रतिवादी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी।

11. हमने उपस्थित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचारपूर्वक विचार किया है और विवादित आदेश और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

12. प्रथम उत्तरदाता की दादी अट्टिली नरसय्यम्मा की मृत्यु 15.9.1977 पर हुई। यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत नोटिस के साथ खंड 8 (1) के तहत मसौदा वक्तव्य 30.11.1977 पर जारी किया गया है।उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार किया कि यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत उक्त नोटिस अट्टिली नरसय्यम्मा को नहीं दिया

गया था और कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

> "...उचित कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा मृतक की संपत्ति के उचित प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति में में, मृत व्यक्ति के खिलाफ की गई कोई भी कार्यवाही शुरू आरम्भतः ही पूरी तरह आरम्भतः अमान्य है और इसलिए यह सुरक्षित रूप आरम्भतः कहा जा सकता है कि स्थापना के समय दिनांकित कार्यवाही पूरी तरह आरम्भतः अमान्य, अवैध और गैर-कानूनी है और किसी भी प्रकृति के उद्देश्य के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसी कोई बाद की कार्यवाही तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि मूल आदेश वैध न हो और कानून के अनुसार उचित निर्धारण न हो।"

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यू. एल. सी. आर. अधिनियम के प्रावधान प्रकृति में ज़ब्त करने वाले हैं जो किसी व्यक्ति को संपत्ति में उसके मूल्यवान अधिकार से वंचित करते हैं। जब विधानमंडल कहता है कि सक्षम प्राधिकारी खंड 8 की उप-खंड (4) के तहत प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विधिवत विचार करेगा, तो यह सक्षम प्राधिकारी पर कर्तव्य डालता है कि वह संबंधित व्यक्ति पर खंड 8 (3) के तहत मसौदा विवरण को इस तरह से लागू करे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मसौदा विवरण संबंधित व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई कारण होने की स्थिति में अपनी आपत्तियां दर्ज करने में सक्षम बनाता है। ऐसा अवसर हो सकता है जब यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 6 (1) के तहत बयान दाखिल करने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, लेकिन यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत मसौदा बयान के साथ नोटिस जारी किए जाने से पहले और खंड 9 के तहत सक्षम

प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या 13 के तहत अंतिम निर्धारण से पहले। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यू. एल. सी. आर. अधिनियम के प्रावधान प्रकृति में ज़ब्त करने वाले हैं जो किसी व्यक्ति को संपत्ति में उसके मूल्यवान अधिकार से वंचित करते हैं।जब विधानमंडल कहता है कि सक्षम प्राधिकारी खंड 8 की उप-खंड (4) के तहत प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विधिवत विचार करेगा, तो यह सक्षम प्राधिकारी पर कर्तव्य डालता है कि वह संबंधित व्यक्ति पर खंड 8 (3) के तहत मसौदा विवरण को इस तरह से लागू करे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मसौदा विवरण संबंधित व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई कारण होने की स्थिति में अपनी आपत्तियां दर्ज करने में सक्षम बनाता है।ऐसा अवसर हो सकता है जब यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 6 (1) के तहत बयान दाखिल करने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, लेकिन यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत मसौदा बयान के साथ नोटिस जारी किए जाने से पहले और खंड 9 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 10 (3) के तहत अंतिम निर्धारण से पहले ऐसी परिस्थितियों में, मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना है और सक्षम प्राधिकारी को कानूनी प्रतिनिधियों से प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार करना है।

14. हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह देखा गया है कि पहले प्रतिवादी सहित बेटों, बेटियों और पोते-पोतियों ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया है। अट्टिली नरसय्यम्मा ने खंड 6 (1) के तहत एक घोषणा दायर की थी और इसे सी. सी. सं.5443/1976 के रूप में क्रमांकित किया गया था। उनके बेटों, बेटियों और पोते-पोतियों (i) अटिली अन्नपूर्णा, (ii) अटिली मालामाम्बा, (iii) अटिली नरसामाम्बा, (iv) अटिली अप्पलास्वामी-(प्रथम

प्रतिवादी) (v) अटिली वेंकट राव, (vi) अटिली विश्वनाथ राव और (vii) अटिली पेडा वेंकट रमण मूर्ति ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 6 (1) के तहत अपने बयान दायर किए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर कुछ हद तक खाली भूमि का दावा किया है।सक्षम प्राधिकारी ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत नोटिस के साथ खंड 8 (1) के तहत एक मसौदा बयान जारी किया, जिसमें अटिली नरसय्यम्मा को एस. नं.29/1,30/1,30/2 और 30/3 में कप्पारदा गाँव के 38,781 वर्ग किलोमीटर की सीमा तक अतिरिक्त भूमि धारक के रूप में निर्धारित किया गया। खंड 8 (3) के तहत मसौदा बयान और नोटिस की प्रति उनके बेटों, बेटियों और पोते-पोतियों को दी गई है, जिसमें यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 6 (1) के तहत अपना बयान दायर करने वाले पहले प्रतिवादी भी शामिल हैं। यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत जारी किए गए उक्त नोटिस के जवाब में, पुत्रों, बेटियों और पोते-पोतियों, अर्थात् उपरोक्त घोषणाकर्ताओं ने अपनी व्यक्तिगत आपत्तियां दायर की हैं और उन सभी का प्रतिनिधित्व उनके वकील द्वारा से किया गया है। अपनी आपत्तियों में, अट्टिली नरसय्यम्मा के बेटों, बेटियों और पोते-पोतियों ने निम्नलिखित आधार उठाएः- (i) यह कि 15.7.1974 दिनांकित एक पारिवारिक व्यवस्था थी, जिसके अनुसरण में, प्रत्येक घोषणाकर्ता अपने-अपने शेयरों के कब्जे और आनंद में है; (ii) अटिली नरसयम्मा ने एक वसीयत निष्पादित की थी और संपत्तियों को वसीयत किया था; (iii) अटिली नरसयम्मा ने डीजल लोको शेड कर्मचारियों और एस. ई. के पक्ष में 25.8.1974 दिनांकित बिक्री समझौते को निष्पादित किया था। एस. एन. में 6 एकड़ भूमि की सीमा तक रेलवे कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति (अपीलार्थी)। कप्पाराडा गाँव के 30/1,30/2 (P) और भूमि की उक्त सीमा को उद्घोषक के अधिकतम सीमा क्षेत्र की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।

15. प्रत्यर्थी सं.2 और 3 द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र में, यह कहा गया है कि मसौदा बयान के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने सभी व्यक्तिगत घोषणाकर्ताओं और उनके अधिवक्ताओं दोनों को जांच के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए। यह माना जाता है कि 3.4.1978 से ही, उद्घोषकों ने एक या दूसरी याचिका पर स्थगन की मांग की है और इस तरह वे मसौदा बयान के खिलाफ आपत्तियां दायर करने के बाद से लगभग पांच वर्षों से जांच के लिए नहीं आए हैं। हमारे विचार में अपनी आपत्तियां दायर करने वाले बेटों, बेटियों और पोते-पोतियों को पर्याप्त अवसर दिया गया था और उनकी आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (1) के तहत जारी किए गए मसौदा बयान की पुष्टि करते हुए यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (4) के तहत आदेश पारित किया और उसके बाद, यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 9 के तहत आवश्यक अंतिम बयान जारी किया गया है।वास्तव में, अटिली नरसय्यम्मा के कानूनी प्रतिनिधियों को संपत्ति पर अपने दावे को साबित करने के लिए अपनी आपत्तियां दर्ज करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।ऐसी स्थिति में, कानूनी प्रतिनिधियों को यह दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया था क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था, जबकि संक्षेप में उन्होंने वास्तव में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जांच के सभी चरणों में भाग लिया है।

16. अपने दिनांकित 5.1.1982 आदेश में सक्षम प्राधिकारी ने इस प्रकार कहाः-

> "प्रारूप वक्तव्य उद्घोषक श्रीमती को दिया गया था। 2.2.1978 पर अट्टिली नरसय्यम्मा खंड 8 (1) के तहत उक्त मसौदा वक्तव्य के खिलाफ श्रीमती को जारी किया गया।अट्टिली नरसय्यम्मा सहित सभी आठ उद्घोषकों ने आपत्ति याचिकाएं दायर की हैं जो इस कार्यालय में 28.2.1978 पर प्राप्त हुई थीं।"

उपरोक्त अवलोकन, निश्चित रूप से, तथ्यात्मक रूप से गलत है।अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष, अटिली विश्वनाथ राव ने रिकॉर्ड पर कानूनी प्रतिनिधियों को लागू न करने पर आपत्ति उठाते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पर हमला किया। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही का उल्लेख करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि अटिली विश्वनाथ राव और स्वर्गीय अटिली नरसय्यम्मा के अन्य बेटों और बेटियों को पूरी कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड में लाया गया है और उन्हें कानून के तहत आवश्यक कार्यवाही का नोटिस दिया गया है, जिसद्वारा अटिली नरसय्यम्मा के गैर-कानूनी प्रतिनिधियों की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है।

17. घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अटिली नरसय्यम्मा के बेटे, बेटियां और पोते-पोतियों ने पहली प्रतिवादी सहित पूरी कार्यवाही में भाग लिया और उन्होंने यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 6 (1) के तहत घोषणा दायर की है और यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 8 (3) के तहत जारी नोटिस के जवाब में अपनी आपत्तियां भी दायर की हैं। वास्तव में, जांच से ही, पहले प्रतिवादी सहित उद्घोषकों का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ताओं द्वारा से किया गया था।दिनांक 1 का आदेश पारित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी आपत्तियों पर विस्तार से विचार किया गया था और उसके बाद, अधिनियम की खंड 9 के तहत आवश्यक अंतिम विवरण जारी किया गया है।यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 10 (1) के तहत अधिसूचना और खंड 10 (3) के तहत घोषणा जारी की गई और उन्हें क्रमशः 24.2.1983 और 22.10.1990 पर ए. पी. राजपत्र में प्रकाशित किया गया।पहले प्रतिवादी अटिली अप्पाला स्वामी और उनके पिता अटिली पेडा वेंकट रमण मूर्ति इस मामले का जोरदार तरीके से पीछा कर रहे थे। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र में, पहले प्रतिवादी को एक परिचित वकील और एक पूर्व सरकारी

वकील बताया गया है। जबकि ऐसा है, पहला प्रतिवादी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही की अज्ञानता और उस पर अपनी भागीदारी का अनुरोध नहीं कर सकता है।

18. यू. एल. सी. आर. अधिनियम में एक घोषणाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जो बाद में घोषणा दायर करने के बाद मर जाता है।यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 31 के मुकदमा (ए) से (ई) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक मुकदमे की सुनवाई करते समय दीवानी अदालत की सभी शक्तियां दी गई हैं। यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 31 के खंड (च) में प्रावधान है कि अन्य मामलों के लिए भी, यह निर्धारित किया जा सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।यह निहितार्थ से दर्शाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के पूरे प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं।यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 46 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाती है। खंड 46 की उप-खंड (2) का खंड (एन) केंद्र सरकार को खंड 31 के खंड (एफ) के तहत सक्षम प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान करने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है।हमारे सामने यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रखा गया था कि ऐसा कोई नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था या सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान लागू किए गए हैं।

19. पूरा करने के लिए, हम आदेश XXII नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का उल्लेख कर सकते हैं जो सी. पी. सी. में प्रासंगिक प्रावधान है जो उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें कई वादी या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है।आदेश XXII नियम 2, सी. पी. सी. निम्नानुसार हैः-

"2. प्रक्रिया जहाँ कई वादी या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है- जहां एक से अधिक अभियोक्ता या प्रतिअभियोक्ता हैं, और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, और जहां मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित अभियोक्ता या अभियोक्ता या केवल जीवित प्रतिअभियोक्ता या प्रतिमुकदमाियों के खिलाफ रहता है, वहां न्यायालय उस प्रभाव की प्रविष्टि रिकॉर्ड पर कराएगा, और मुकदमा जीवित अभियोक्ता या अभियोक्ता के कहने पर, या जीवित प्रतिअभियोक्ता या प्रतिमुकदमों के खिलाफ आगे बढ़ेगा।"

जब किसी मृत अभियोक्ता के कानूनी प्रतिनिधि पहले से ही अपनी व्यक्तिगत क्षमता में रिकॉर्ड में हैं, तो आदेश XXII नियम 2 सी. पी. सी. के तहत केवल एक ध्यान दें पर्याप्त है। जैसा कि पहले देखा गया है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में, अट्टिली नरसय्यम्मा के बेटे, बेटियां और पोते-पोतियां पहले से ही अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दर्ज थे।हालांकि, प्रथम प्रतिवादी मृतक अटिली नरसय्यम्मा के कानूनी प्रतिनिधियों पर औपचारिक रूप से कार्रवाई न करने या मृतक अटिली नरसय्यम्मा के कानूनी प्रतिनिधियों पर औपचारिक नोटिस न देने के कारण किसी भी पूर्वाग्रह की शिकायत नहीं कर सकता है।

20. समीक्षा याचिका में, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने घटनाओं के क्रम और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पहले प्रतिवादी सहित बेटों, बेटियों और पोते-पोतियों की पूर्ण भागीदारी को नजरअंदाज कर दिया।पुनरीक्षण न्यायालय के पास केवल एक सीमित अधिकार क्षेत्र है जो आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में उपयोग की गई भाषा द्वारा निर्धारित निश्चित सीमाओं द्वारा सीमित है। यह तीन निर्दिष्ट आधारों पर पुनरीक्षण की अनुमति दे सकता है, अर्थात्:- (i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज, जो

उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, आवेदक की जानकारी में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था; (ii) रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि; या (iii) किसी अन्य पर्याप्त कारण से।नई सामग्री की खोज के आधार पर समीक्षा के लिए आवेदन पर बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और इसे बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

21. 15.9.1997 पर अट्टिली नरसयम्मा की मृत्यु का तथ्य और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधियों को लागू न करने के बारे में याचिका सभी चरणों में यानी अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ एकल न्यायाधीश के समक्ष और रिट अपील में भी उठाई गई थी। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अटिली नरसयम्मा के बेटों, बेटियों और पोते-पोतियों की भागीदारी पर विचार करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश (रिट याचिका सं.18340/2001) ने माना कि अटिली नरसयम्मा के कानूनी प्रतिनिधियों को अटिली नरसयम्मा की ओर से अपनी आपत्तियां रखने का पर्याप्त अवसर था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।रिट अपील संख्या 1840/2008 में, खण्ड पीठ ने इस पहलू पर भी विचार किया और पाया कि सभी कानूनी प्रतिनिधि पहले से ही रिकॉर्ड में थे और उन्होंने कार्यवाही में भाग लिया और कानूनी प्रतिनिधियों को लागू नहीं करने की शिकायत नहीं कर सकते। समीक्षा याचिका में अपने स्वयं के आदेश और फिर यू. एल. सी. आर. अधिनियम के तहत अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि उचित कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा मृतक अट्टिली नरसयम्मा की संपत्ति का कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं था और एक मृत व्यक्ति के खिलाफ की गई कोई भी कार्यवाही पूरी तरह आरम्भतः अमान्य है और दिनांकित 5.1.1982 आदेश अमान्य और अवैध है। यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में अट्टिली नरसय्यम्मा के

बेटों, बेटों और पोते-पोतियों की भागीदारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और उक्त आपत्ति पर सभी मंचों द्वारा विचार किया गया और उसे नकार दिया गया।जहाँ तक यू. एल. सी. आर. निरसन अधिनियम 1999 की प्रयोज्यता का संबंध है, आक्षेपित आदेश में केवल ऐसी टिप्पणियाँ की गई हैं कि "निरसन अधिनियम को देखते हुए सभी कार्यवाहियों का कोई प्रभाव नहीं है।"हमारे विचार में, समीक्षा याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश गलत है और टिकाऊ नहीं है।

22. भूमि का निवेशःखंड 10 की उप-खंड (1) में कहा गया है कि विवरण की सेवा के बाद, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक भूमि का विवरण देते हुए एक अधिसूचना जारी करनी होगी।सरकारी राजपत्र में आम जनता की जानकारी के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की जानी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि ऐसी खाली भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और ऐसी खाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के दावे उनके द्वारा किए जाने चाहिए, जिसमें ऐसी भूमि में उनके हितों की प्रकृति का विवरण दिया जाए।खंड 10 की उप-खंड (2) में कहा गया है कि खाली भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के दावों पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे दावों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करनी होगी और ऐसे आदेश पारित करने होंगे जो वह उचित समझे।खंड 10 की उप-खंड (3) में कहा गया है कि उप-खंड (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद सक्षम प्राधिकारी को यह घोषणा करनी होगी कि खंड 10 की उप-खंड (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि, ऐसी तारीख से प्रभावी होगी, जो घोषणा में निर्धारित की जाए, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई मानी जाएगी।उस आशय की घोषणा के प्रकाशन पर यह समझा जाएगा कि ऐसी भूमि इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि से सभी बाधाओं से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से राज्य सरकार में निहित थी।

23. यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 10 (3) के तहत राजपत्र में 38,781 वर्ग किलोमीटर की अतिरिक्त भूमि का प्रकाशन किया गया है।यह समझा जाएगा कि यह आत्यन्तिक रूप से राज्य सरकार में निहित है जो सभी बाधाओं से मुक्त है। 31.1.1991 पर खंड 10 (5) के तहत खाली भूमि के कब्जे को सौंपने के लिए नोटिस जारी किया गया था।जहाँ तक अधिशेष भूमि को सरकार को सौंपने का सवाल है, वहाँ भारी सामग्री है और तदनुसार, निहित करना निर्णायक हो गया।

24. निरसन अधिनियम 1999 का प्रभावःशहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 को आंध्र प्रदेश राज्य में 27.3.2008 से अपनाया गया था।प्रथम प्रतिवादी का तर्क है कि चूंकि कब्जा नहीं लिया गया था, इसलिए यू. एल. सी. आर. निरसन अधिनियम 1999 पूरी तरह से लागू है और भूमि सीमा की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है।प्रथम प्रतिवादी निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 और 4 पर निर्भर करता है।इसलिए, निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 और 4 का उल्लेख करना उचित होगा जो निम्नानुसार हैः-

> "3. बचत हो रही है- (1) मूल अधिनियम के निरसन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा -
>
> (क) खंड 10 की उप-खंड (3) के तहत किसी भी खाली भूमि को निहित करना, जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को सौंप दिया गया है;
>
> (ख) खंड 20 की उप-खंड (1) के तहत छूट देने वाले किसी भी आदेश की वैधता या उसके तहत की गई कोई कार्रवाई, इसके विपरीत किसी भी अदालत के किसी भी फैसले के बावजूद;

(ग) खंड 20 की उप-खंड (1) के तहत छूट देने की शर्त के रूप में राज्य सरकार को किया गया कोई भी भुगतान।

(2) कहाँ -

(क) ऐसा कोई भूमि जो मूल अधिनियम की खंड 10 की उप-खंड (3) के तहत राज्य सरकार में निहित मानी जाती है, लेकिन जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया गया है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान किया गया है, तो ऐसी भूमि को तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार को वापस नहीं कर दी गई हो।

4. कानूनी कार्यवाही में उपशमन- इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपशमन करना मूल अधिनियम के तहत किए गए या किए जाने वाले किसी भी आदेश से संबंधित सभी कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी।

बशर्ते कि यह खंड मूल अधिनियम की खंड 11,12,13 और 14 से संबंधित कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगी, जहां तक ऐसी कार्यवाहियां उस भूमि से संबंधित हैं, जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया है।"

25. सरकार और अपीलकर्ता के हाथों दी गई दलील यह थी कि अपीलकर्ता-समिति और जिन आवंटनकर्ताओं को भूखंड आवंटित किए गए थे, उनके कब्जे को मान्यता देते हुए सरकार ने जी ओ एमएस 1900 दिनांक 20.12.2006 जारी किया जो आंध्र प्रदेश राज्य में निरसन अधिनियम को अपनाने से बहुत पहले है और इसलिए, निरसन अधिनियम अपीलकर्ता-समिति को आवंटित उक्त 6 एकड़ पर लागू नहीं होता है। जहाँ तक शेष सीमा है, सरकार का तर्क है कि इसका वास्तविक कब्जा निरसन अधिनियम से बहुत पहले एक पंचनामा द्वारा लिया गया था और इसलिए, निरसन अधिनियम लागू नहीं होता है।

26. यू. पी. राज्य बनामहरि राम, (2013) 4 एस. सी. सी. 280, इस न्यायालय ने निरसन अधिनियम 1999 में बचत खंड के संदर्भ में यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 10 (3) के तहत "मानित निहित" के संबंध में प्रश्न पर विचार किया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निरसन अधिनियम 1999 के तहत खंड को बचाने के उद्देश्य से, वास्तविक कब्जा राज्य द्वारा लिया जाना आवश्यक है न कि कानूनन रूप से।हरि राम के मामले के पैराग्राफ (31), (34) और (35) में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

> "31. हमारे विचार में, खंड 10 की उप-खंड (3) में "निहित" करने का अर्थ है आत्यन्तिक रूप से अधिकार निहित करना और कब्जा नहीं करना, हालांकि किसी व्यक्ति के स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने या कब्जा देने के रास्ते में कुछ भी नहीं है।महाराज 9. बनाम यू. पी. राज्य [(1977) 1 एस. सी. सी. 155] मामले में न्यायालय ने यू. पी. जमींदारी उत्सादन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की खंड 117 (1) की व्याख्या करते हुए कहा कि "निहित" एक फिसलन भरा शब्द है और इसके कई अर्थ हैं और संदर्भ पाठ को नियंत्रित करता है और

उद्देश्य और योजना अर्थ की विशेष शब्दार्थ छाया या बारीकियों को प्रस्तुत करती है।.....

.....

34. खंड 10 की उप-खंड (5) में पहली बार "अधिकार" की बात की गई है जिसमें कहा गया है कि जहां कोई भूमि खंड 10 की उप-खंड (3) के तहत राज्य सरकार में निहित है, वहां सक्षम प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जो इसके कब्जे में हो सकता है, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को समर्पण करने या कब्जा हस्तांतरित करने का आदेश दे सकता है।

35. यदि खंड 10 की उप-खंड (3) के तहत दो उपबंधों द्वारा राज्य सरकार को वास्तविक कब्जा पहले ही दे दिया गया है, तो खंड 10 की उप-खंड (5) के तहत "जहां कोई भूमि निहित है" अभिव्यक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।खंड 10 की उप-खंड (3) के तहत कब्जे का समर्पण या हस्तांतरण स्वैच्छिक हो सकता है ताकि व्यक्ति को अधिनियम की खंड 11 के तहत दिए गए मुआवजे को जल्दी मिल सके।एक बार जब कोई स्वैच्छिक समर्पण या कब्जे की डिलीवरी नहीं होती है, तो आवश्यक रूप से राज्य सरकार को आत्मसमर्पण या कब्जा देने के लिए खंड 10 की उप-खंड (5) के तहत लिखित रूप में नोटिस जारी करना पड़ता है।खंड 10 की उप-खंड (5) शांतिपूर्वक समर्पण करने और कब्जा देने की स्थिति की कल्पना

करती है, जबकि खंड 10 की उप-खंड (6) बलपूर्वक बेदखल करने की स्थिति पर विचार करती है।"

27. प्रथम प्रत्यर्थी ने हरि राम के मामले के पैराग्राफ (42) में टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा रखा जो इस प्रकार हैः-

"42. खंड 10 की उप-खंड (3) के तहत भूमि को केवल सौंपने से राज्य सरकार को खाली भूमि पर वास्तविक कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक कि 18.3.1999 से पहले खाली भूमि का स्वैच्छिक समर्पण नहीं किया गया हो। राज्य को यह स्थापित करना होगा कि खंड 10 की उप-खंड (5) के तहत खाली भूमि का स्वैच्छिक समर्पण या समर्पण और शांतिपूर्ण कब्जे का वितरण या खंड 10 की उप-खंड (6) के तहत जबरन बेदखल किया गया है।इनमें से किसी भी स्थिति को स्थापित करने में विफल रहने पर, भूमि मालिक या धारक निरसन अधिनियम की खंड 4 के लाभ का दावा कर सकते हैं। इस अपील में राज्य सरकार उन स्थितियों में से किसी को भी स्थापित नहीं कर सकी और इसलिए उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि प्रतिवादी निरसन अधिनियम की खंड 4 का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।''

प्रथम प्रत्यर्थी का तर्क है कि अधिशेष भूमि का कब्जा कभी भी सरकार को नहीं सौंपा गया था और हरि राम के मामले में उपरोक्त टिप्पणियां पूरी तरह से लागू हैं और निरसन अधिनियम के आधार पर, भूमि सीमा की कार्यवाही समाप्त हो गई थी।

28. जैसा कि पहले देखा गया है, इसका कुल विस्तार 38,781 वर्ग किलोमीटर है। 38, 781 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त भूमि का विवरण अधिशेष घोषित किया गया। यह निम्नानुसार हैः

गाँव (अतिरिक्त)	सर्वेक्षण सं	अधिशेष भूमि (वर्ग मीटर)
कप्पारदा	29/1	3,574
कप्पारदा	30/1	10,036
कप्पारदा	30/2	24,200
कप्पारदा	30/3	971
	कुल	38,781

29. हमारे विचार में, निरसन अधिनियम के प्रभाव पर दो अलग-अलग विस्तारों के संबंध में अलग से विचार किया जाना चाहिए।, (1) 6.00 कप्परदा गाँव के सर्वेक्षण सं. 30/1 और 30/2 में एकड़ भूमि जो GO.Ms सं.1900 में अपीलार्थी-सोसायटी को आवंटित की गई है। दिनांक 20.12.2006 और जो अपीलार्थी-सोसायटी के आवंटी-सदस्यों के कब्जे में है; (2) सर्वेक्षण सं. 29/1 और 30/3 में अधिशेष भूमि और सर्वेक्षण सं. 30/1 और 30/2 में शेष सीमा।

30. स्वर्गीय अट्टिली नरसय्यम्मा ने सर्वेक्षण संख्या 30/1 और 30/2 में भूमि के 25.8.1974 पर अपीलकर्ता-सोसायटी के पक्ष में 6 एकड़ की सीमा तक बिक्री का समझौता किया था और रु. 1,52,000-की राशि प्राप्त की थी। 10.3.1990 पर, अपीलकर्ता-सोसायटी ने अट्टिली नरसय्यम्मा के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अपीलकर्ता सोसायटी ने एक करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। 4,00,000-प्रति एकड़ और रू.50,000/-

का अग्रिम भुगतान किया गया था। 3.6.1996 पर, अपीलार्थी-समिति ने उसी संपत्ति के संबंध में अट्टिली नरसय्यम्मा के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ बिक्री का एक और समझौता किया। यह समझौता 1.4 एकड़ के संबंध में था, जिसके बदले में रुपये की पूरी बिक्री का भुगतान किया गया था और उक्त सीमा का कब्जा अपीलार्थी-सोसायटी को सौंप दिया गया था और इसे भूखंडों में विकसित किया गया था जो सोसाइटी के सदस्यों को आवंटित किए गए थे। 15.1.2001 पर, अपीलार्थी-सोसायटी और अट्टिली नरसय्यम्मा के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच शेष 4.6 एकड़ के संबंध में बिक्री का एक और समझौता किया गया था, जिसमें प्रति एकड़ 1,00,000 रुपये की संशोधित दर थी। 3,00,000-का भी भुगतान किया गया था।6.2.2003 पर, GO.Ms के आधार पर। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले से ही तीसरे पक्ष के कब्जे में यू. एल. सी. आर. अधिनियम के तहत अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। अपीलकर्ता सोसायटी ने समझौते के तहत 6 एकड़ के आवंटन के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया। उसी के जवाब में, सरकार ने GO.Ms सं.340 जारी किया। दिनांक 5.3.2003 और इस संबंध में कुछ दिशानिर्देशों में ढील देकर अपीलकर्ता के मामले पर अनुकूल रूप से विचार करने का निर्णय लिया और कुछ विवरण मांगे। पहले प्रतिवादी ने इस आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका 1216/2004 दायर की।

31. विशेष अधिकारी और सक्षम प्राधिकरण, शहरी भूमि सीमा, विशाखापत्तनम ने राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि के यू. एल. सी. आर. अधिनियम की खंड 23 (4) के तहत आवंटन के लिए दायर आवेदन के आधार पर और कप्पाराडा गांव के सर्वेक्षण सं30/1 और 30/2 में अपीलकर्ता-सोसायटी के सदस्यों के कब्जे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए।जी ओ एमएससं. 1900 दिनांक 20.12.2006 अपीलार्थी-सोसायटी को 6 एकड़ भूमि आवंटित करने और इस तरह उनके कब्जे को नियमित करने के लिए जारी किया गया था। उक्त सरकारी आदेश में कहा गया है कि सोसायटी ने इस तरह के

आवंटन के लिए मुआवजे के लिए आवश्यक राशि का भी भुगतान किया है।फिर से इस आदेश को पहले प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका सं.735/2007 दायर करके चुनौती दी गई और दोनों रिट याचिकाओं को लंबित बताया गया है।

32. हम इस बात से अवगत हैं कि दो रिट याचिकाएं। डब्ल्यू. पी. सं.1216/2004 और डब्ल्यू. पी. सं.735/2007 को उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसमें अपीलार्थी-सोसायटी को 6 एकड़ भूमि के आवंटन को चुनौती दी गई है। उनके इस तर्क के समर्थन में कि अपीलकर्ता सोसायटी को आवंटित भूमि खाली है, प्रथम प्रतिवादी द्वारा कुछ तस्वीरें दायर की गईं। जहां तक उक्त 6 एकड़ भूमि का संबंध है, यह दिखाने के लिए भारी सामग्री है कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 27.3.2008 पर यू. एल. सी. आर. अधिनियम को अपनाने से पहले ही कब्जा अपीलार्थी-सोसायटी को सौंप दिया गया था। दिनांक 10.3.1990 समझौते में निम्नलिखित शर्तों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि झाड़ियों आदि को साफ करने के लिए कब्जा अपीलार्थी-समिति को सौंप दिया गया था।:

> "उपरोक्त समझौतों के अनुसरण में प्रथम पक्ष ने दूसरे पक्ष को झाड़ियों को साफ करने और ले आउट बनाने के उद्देश्य से भूमि का सर्वेक्षण करने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति से अग्रिम के रूप में रू 50,000/- प्राप्त किया और द्वितीय पक्ष और प्रथम पक्ष इसके द्वारा इसे स्वीकार करते हैं।"

दिनांकित 3.6.1996 समझौते में कब्जे के वितरण और सदस्यों को किए गए अस्थायी आवंटन के संबंध में खंड भी शामिल हैः-

> "1 एकड़ 40 सेंट की पूरी बिक्री का भुगतान उपरोक्त 12 सदस्यों द्वारा किया गया था और सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव के परामर्श से

और सोसाइटी द्वारा अपने दिनांकित पत्र 8.8.1994 के माध्यम से किए गए अस्थायी आवंटन के आधार पर उन्हें कब्जा दिया जाता है और उन्होंने प्लॉट 45 से 56 की लेआउट योजना के अनुसार अपने भूखंडों को बाड़ से संलग्न किया है।"

दिनांक 15.1.2001 समझौते में कब्जा सौंपने और लेआउट बनाने और समाज को सड़क तक पहुंच का अधिकार प्रदान करने का भी उल्लेख किया गया है।-

"विक्रेता खरीदारों को 3 महीने की अवधि के भीतर भूमि को समतल करने और योजना के अनुसार सड़कों और भूखंडों का सीमांकन करने की अनुमति देने के लिए सहमत होते हैं।

खरीदार इस बात पर सहमत हैं कि खाका बिछाने और सड़कें बिछाने के बाद, विक्रेता उस सड़क का उपयोग करने का हकदार होगा जो अनुसूची भूमि संस्पर्शी उनकी दूसरी भूमि है।विक्रेता अपनी भूखंडों में जाने के लिए लेआउट में बनाई गई सड़क तक पहुँच देने के लिए सहमत होते हैं, यदि विक्रेताओं के लिए आवश्यक हो तो भूमि जो अनुसूची भूमि से संस्पर्शी है।विक्रेताओं और खरीदार दोनों ने ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के लिए सहमति व्यक्त की और विशाखापत्तनम में 15 जनवरी 2001 को अपने हस्ताक्षर किए।"

33. निरसन अधिनियम की खंड 3 (1) के संदर्भ में, खंड 10 की उप-खंड (3) के तहत किसी भी खाली भूमि को निहित करना, जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही ले लिया गया है, मूल अधिनियम के निरसन से यह प्रभावित नहीं होगा। ऊपर निर्दिष्ट विभिन्न समझौतों की शर्तें और जी ओ एमएससं.1900 दिनांक

20.12.2006 की अवधि भी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि कब्जा पहले से ही अपीलार्थी-समिति को सौंप दिया गया था और संबंधित आबंटियों ने भूखंडों पर कब्जा कर लिया था। यह भी ध्यान दें योग्य है कि कहा जाता है कि 38 सदस्य-आवंटनकर्ताओं ने पहले ही अपना निर्माण पूरा कर लिया है और कुछ अन्य ने अपने भूखंडों पर बाड़ लगा ली है।पहले के समझौतों और सरकारी आदेश जी ओ एमएससं.1900 दिनांक 20.12.2006 के आधार पर, जिस तारीख को आंध्र प्रदेश राज्य में निरसन अधिनियम अपनाया गया था, यानी 27.3.2008 पर, अपीलार्थी-सोसायटी के पास पहले से ही सर्वेक्षण संख्या 30/1 और 30/2 में 6 एकड़ जमीन थी और निरसन अधिनियम 6 एकड़ की उक्त सीमा तक लागू नहीं होता है।

34. जैसा कि पहले देखा गया है, सोसायटी को भूमि मुख्य रूप से इस आधार पर आवंटित की गई थी कि आवंटित भूखंडों पर सदस्य-आवंटनकर्ताओं का कब्जा था। सोसायटी के सदस्यों द्वारा 6 एकड़ भूमि पर कब्जा बिक्री के पूर्व समझौतों के आधार पर स्पष्ट है। जब हमने सोसायटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्णकुमार से पूछा कि क्या समझौतों के संदर्भ में पूरी बिक्री का भुगतान विक्रेताओं को किया गया था, तो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कहा कि विक्रेताओं को लगभग तीस लाख रुपये का भुगतान किया गया है। विक्रेताओं को भुगतान किए गए प्रतिफल, विक्रेताओं को देय शेष राशि और आवंटन के बदले सरकार को राशि का भुगतान किया गया है या नहीं, इसका सही विवरण स्पष्ट नहीं है।इन पहलुओं पर हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई थी। बिक्री के समझौते करने और आवंटन प्राप्त करने के बाद, इक्विटी की मांग है कि सोसाइटी को सरकार को भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, के अलावा विक्रेताओं को पूरी बिक्री का भुगतान करना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा विक्रेताओं को देय शेष बिक्री प्रतिफल राशि का निर्धारण करने के बजाय, जहाँ तक 6 एकड़ भूमि का संबंध है, यह मामला, हमारी राय में, केवल अपीलार्थी-सोसायटी द्वारा विक्रेताओं को देय शेष बिक्री

प्रतिफल का निर्धारण करने के सीमित उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जा सकता है-अटिली नरसय्यम्मा के कानूनी उत्तराधिकारी।

35. कहा जाता है कि जी ओ एमएससं.1900 दिनांक 20.12.2006 के अंतर्गत आने वाली भूमि को छोड़कर, अधिशेष भूमि के शेष हिस्से का कब्जा दिनांक 4.1.2008 के पंचनामा के आधार पर लिया गया था।रिट याचिका सं.18340/2001 में, उच्च न्यायालय द्वारा 12.9.2001 पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी और यह 6.11.2008 यानी रिट याचिका के निपटारे तक लागू रही। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, पंचनामे के प्रभाव की जांच की जानी चाहिए और इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वास्तविक कब्जा सरकार या राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया था। जहाँ तक अधिशेष भूमि के शेष विस्तार का संबंध है, निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होंगे।, (i) क्या राज्य सरकार द्वारा वास्तविक भौतिक कब्जा लिया गया था; (ii) जब उच्च न्यायालय द्वारा 12.9.2001 पर दिया गया अंतरिम आदेश लागू था, तो दिनांक 4.1.2008 का क्या प्रभाव है; (iii) क्या आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 27.3.2008 पर अपनाया गया निरसन अधिनियम लागू है और क्या पहला प्रतिवादी निरसन अधिनियम 1999 की खंड 4 का लाभ प्राप्त करने का हकदार है, इस पर विचार किया जाना है। हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा इन प्रश्नों की जांच करने के बजाय, उपरोक्त प्रश्नों की जांच के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।

36. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय का विवादित आदेश समीक्षा याचिका डब्लयू पी एम पी संख्या 1540/2009 में पारित किया गया और खण्ड पीठ का आदेश डब्ल्यू ए सं 1840/2008 में पारित किया गया। दिनांक 2.2.09 को अलग कर दिया जाता है और उपरोक्त चर्चा और पैराग्राफ संख्या (34) और (35) में निहित निर्देशों के आलोक में रिट अपील सं.1840/2008 पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।उच्च

न्यायालय सभी संबंधित पक्षों को अतिरिक्त शपथ पत्र और जवाबी शपथ पत्र दायर करने और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, दायर करने और कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।